समक्ष आर.एन.मित्तल जे.

परमेश्री, -अपीलकर्ता;

बनाम

नौरता,- प्रतिवादी।

सिविल विविध. क्रमांक 2819-सी 1983.

R.S.A.R.S.A.o 19517of 1971

10 मई 1984.

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5)–धारा। 148–निश्चित राशि के भुगतान पर कब्जे के लिए सशर्त डिक्री पारित–वह समय जिसके भीतर राशि का भुगतान किया जाना है–न्यायालय–क्या धारा 148 के तहत समय बढ़ाने का हकदार है।

माना गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 148 को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि न्यायालय के पास ऐसे कार्यों को करने के लिए समय बढ़ाने की शक्ति है जो संहिता द्वारा निर्धारित या अनुमत हैं। दूसरे शब्दों में, यह प्रक्रियात्मक आदेशों पर लागू होता है न कि सशर्त आदेशों पर। सशर्त डिक्री के मामले में, न्यायालय समय नहीं बढ़ा सकता है, हालांकि अन्य मामलों में वह ऐसा कर सकता है। इसलिए, यह माना जाता है कि किसी पक्ष द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर कुछ राशि के भुगतान पर कब्जे के लिए सशर्त डिक्री के मामले में, न्यायालय पर्याप्त कारण के लिए संहिता की धारा 148 के तहत भुगतान के लिए समय बढ़ाने का हकदार नहीं है, यदि राशि निर्दिष्ट समय के भीतर जमा नहीं की जाती है। (पैरा 5 और 6)।

धारा 148 के तहत आवेदन धारा 151 सी.पी.सी. के साथ पढ़ा जाए। प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना करते हुए कि यह माननीय न्यायालय तीसरी किस्त के भुगतान का समय 25 अक्टूबर, 1983 तक या इस माननीय न्यायालय के आदेशों के तहत वादी/अपीलकर्ता द्वारा राशि स्वीकार किए जाने तक बढ़ा सकता है।

आवेदक प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता राजेश चौधरी।

अपीलकर्ता की ओर से जे.के. शर्मा, अधिवक्ता, आई.एस. सैनी, अधिवक्ता के साथ।

निर्णय आर.एन.मित्तल, जे.

1. संक्षेप में तथ्य यह है कि वादी के पिता रामसरन की मृत्यु 8-11-1966 को हो गयी थी। प्रतिवादी ने कथित तौर पर रामसरन द्वारा अपने पक्ष में निष्पादित की गई वसीयत के आधार पर अपने पक्ष में भूमि का नामांतरण स्वीकृत करा लिया। वादी ने वसीयत के निष्पादन और वैधता को चुनौती देते हुए कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया, जिसका प्रतिवादी ने विरोध किया। उन्होंने वादी के आरोपों का खंडन किया और आरोप लगाया कि मृतक राम सरन ने सेवाओं के बदले अपने पक्ष में वसीयत विधिवत निष्पादित की थी।

2. ट्रायल कोर्ट ने माना कि राम सरन ने प्रतिवादी के पक्ष में एक वैध वसीयत निष्पादित की। परिणामस्वरूप इसने मुकदमा खारिज कर दिया। वादी की अपील पर प्रथम अपीलीय अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले और डिक्री की पुष्टि की और उसे खारिज कर दिया। इस न्यायालय में दूसरी अपील में पार्टियों के बीच एक समझौता हुआ जिसके अनुसार यह सहमति हुई कि प्रतिवादी द्वारा अपीलकर्ता को 15,000/- रुपये की राशि किश्तों में भुगतान की जाएगी और यदि वह किसी भी किश्त का भुगतान करने में विफल रहता है, वादी के मुकदमे पर फैसला सुनाया जाएगा। मामला मेरे सामने सूचीबद्ध किया गया था और मैंने समझौते के अनुसार निम्नलिखित निर्णय पारित किया:

"दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ है जिसके अनुसार यह सहमति हुई है कि प्रतिवादी 5,000/- रुपये की तीन समान किस्तों में रसीदों के बदले बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अपीलकर्ता को 15,000/- रुपये का भुगतान करेगा। पहली किस्त है 15-10-1982 को या उससे पहले, दूसरी 5 जून 1983 को या उससे पहले, और तीसरी 15-10-1983 को या उससे पहले भुगतान किया जाना है। यदि प्रतिवादी उक्त किश्तों में से किसी एक का भुगतान करने में विफल रहता है, तो अपील की जाएगी स्वीकार कर लिया जाएगा और वादी का मुकदमा डिक्री कर दिया जाएगा। हालाँकि, यदि प्रतिवादी ऊपर बताई गई सभी किस्तों का भुगतान करता है, तो अपील खारिज कर दी जाएगी। समझौता, एक्ज़िबिट सीआई, को निर्णय और डिक्री का हिस्सा माना जाएगा। पार्टियां बची हुई हैं अपनी लागत स्वयं वहन करने के लिए।"

प्रतिवादी समय पर अंतिम किस्त का भुगतान करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, उन्होंने तीसरी किस्त का भुगतान करने के लिए समय बढ़ाने के लिए सिविल पीसी की धारा 151 के साथ पठित धारा 148 के तहत एक आवेदन दायर किया। आवेदन में कहा गया है कि आवेदक, जो 80 वर्ष का था, 5-10-1983 को गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और उस अवधि के दौरान मृत्यु के कगार पर रहा। चलते ही उसने रुपये की व्यवस्था कर ली। 5,000/- और बैंक ड्राफ्ट दिनांक के माध्यम से पैसा भेज दिया। 25-10-1983 श्रीमती को। परमेश्वरी देवी वादी जिसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। आरोप है कि तीसरी और आखिरी किस्त के टेंडर में देरी आवेदक की बीमारी के कारण हुई जो उसके नियंत्रण से बाहर थी। आगे आरोप है कि गांव में देर से बुआई के कारण धान की फसल देर से हुई, इसलिए उनके लिए शेष राशि का इंतजाम करना मुश्किल हो गया। आवेदन का वादी द्वारा विरोध किया गया है जिसने अपने

आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने इस आरोप से भी इनकार किया कि आवेदक किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। अत: प्रार्थना की जाती है कि आवेदन खारिज कर दिया जाये।

3. निर्धारण के लिए मुख्य प्रश्न यह है कि यदि एक निश्चित अवधि के भीतर निश्चित राशि के भुगतान पर कब्जे के लिए एक सशर्त डिक्री किसी पार्टी के पक्ष में पारित की जाती है और वह उस समय के भीतर राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो क्या न्यायालय समय बढ़ाने का हकदार है? धारा 148, Civi1 PC के तहत भुगतान के लिए, पर्याप्त कारण के लिए? आवेदक के विद्वान वकील का कहना है कि न्यायालय के पास संहिता की धारा 148 के तहत समय बढ़ाने की शक्ति है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने महंत राम दास बनाम गंगा दास , एआईआर 1961 एससी 882, श्रीमती का संदर्भ दिया। पेरियाक्कल बनाम श्रीमती। दाक्षायनी , एआईआर 1983 एससी 428, जड़बेंद्र नाथ मिश्रा बनाम श्रीमती। मनोरमा देब्या , एआईआर 1970 कैल 199, गोबर्धन सिंह बनाम बरसाती , एआईआर 1972 सभी 246 (एफबी) और न्यू बंगेश्री बस्तरालय बनाम रमनलाल फुरमा कर्ता, एआईआर 1976 कैल 335।

4. मैंने पक्षों के विद्वान वकीलों को काफी विस्तार से सुना है और उनके तर्कों पर गहन विचार किया है। धारा 148 कहती है कि जहां संहिता द्वारा निर्धारित या अनुमत किसी कार्य को करने के लिए न्यायालय द्वारा कोई अवधि तय की जाती है या दी जाती है, तो न्यायालय समय-समय पर अपने विवेक से ऐसी अवधि बढ़ा सकता है, भले ही मूल रूप से निर्धारित या दी गई अवधि हो सकती है। समाप्त हो गए हैं.

6. धारा को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि न्यायालय के पास ऐसे कार्यों को करने के लिए समय बढ़ाने की शक्ति है जो संहिता द्वारा निर्धारित या अनुमत हैं। दूसरे शब्दों में यह प्रक्रियात्मक आदेशों पर लागू होता है न कि सशर्त आदेशों पर। उपरोक्त दृष्टिकोण में मैं महंत राम दास के मामले (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों से कुछ हद तक मजबूत हुआ हूं। इसे हिदायतुल्ला, जे. (जैसा कि वह तब था) द्वारा इस प्रकार देखा गया (पृष्ठ 883 पर):

"भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए लगातार समय निर्धारित करना कितना अवांछनीय है, जो अदालत को बीच में उत्पन्न होने वाली घटनाओं से निपटने के लिए शक्तिहीन बना देता है, इस अपील में निर्णय लेना आवश्यक नहीं है। ये आदेश अक्सर अनुपयुक्त होने के लिए पर्याप्त होते हैं। ऐसे प्रक्रियात्मक आदेश, हालांकि अनुदेशात्मक (सशर्त आदेशों को छोड़कर), संक्षेप में, आतंकवाद में हैं, ताकि विलंब करने वाले वादी खुद को व्यवस्थित कर सकें और देरी से बच सकें। हालांकि, वे अदालत को होने वाली घटनाओं और परिस्थितियों पर ध्यान देने से पूरी तरह से रोकते नहीं हैं तय समय के भीतर।" (रेखांकित करके जोर दिया गया है)।

उपरोक्त टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि सशर्त डिक्री की आसानी में न्यायालय समय नहीं बढ़ा सकते हैं, हालांकि अन्य मामलों में वह ऐसा कर सकते हैं। उपरोक्त मामले के बाद, पीके

सुकुमारन बनाम सुलेमान खान , एआईआर 1971 मैड 454, एस. महालिंग भट्ट बनाम असनारे बेरी , एआईआर 1973 केर 185, भुजंगराव गणपति बनाम शेषराव राजाराम , एआईआर 1974 बीओएम 104 और कुमारी सुशीला में भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया था। देवी जैन बनाम मोहम्मद शफ़ी, 1982 ए11 एलजे 478। यह पीके सुकुमारन के मामले (सुप्रा) में आयोजित किया गया था जहां एक मुकदमे का फैसला इस शर्त पर किया जाता है कि एक निश्चित राशि का भुगतान एक निर्दिष्ट समय के भीतर किया जाता है और डिफ़ॉल्ट रूप से वह मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा, न्यायालय , निश्चित समय की समाप्ति के बाद, मामले पर सेसीन खो देता है और इसलिए समय नहीं बढ़ा सकता है। धारा 148 की व्याख्या करते समय कुमारी सुशीला देवी जैन के मामले में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गईं (पृ. 479-80 पर):

"यह केवल प्रक्रियात्मक आदेश हैं जिनके संबंध में अनुपालन के लिए समय बढ़ाया जा सकता है। यह सशर्त आदेशों के संबंध में नहीं है, जो स्व-संचालित हैं, इस प्रावधान के तहत समय बढ़ाया जा सकता है।"

मैं उपरोक्त टिप्पणियों से सम्मानपूर्वक सहमत हूं।

6. अब मैं आवेदक के विद्वान वकील द्वारा संदर्भित मामलों पर ध्यान केंद्रित करता हूं। महंथ राम दास का मामला (एआईआर 1961 एससी 882) (सुप्रा) पहले ही ऊपर संदर्भित किया जा चुका है। श्रीमती में. पेरियाक्कल का मामला (एआईआर 1983 एससी 428) (सुप्रा), एक संपत्ति की नीलामी एक डिक्री के अनुसरण में की गई थी जिसे डिक्री-धारक द्वारा खरीदा गया था। निर्णय-देनदार के कानूनी प्रतिनिधियों ने बिक्री के खिलाफ आपत्तियां दर्ज कीं। दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ जिसके द्वारा कानूनी प्रतिनिधि एक विशेष तिथि तक निश्चित राशि जमा करने पर सहमत हुए। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि समझौता किसी मुकदमे में नहीं बल्कि निष्पादन कार्यवाही में हुआ था। इस प्रकार यह आदेश डिक्री के समान नहीं है। जबबेंद्र नाथ मिश्रा के मामले (एआईआर 1970 कैल 199) में प्रतिवादी के खिलाफ एक पक्षीय डिक्री पारित की गई थी, जिसने एक पक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए आवेदन किया था। आवेदन के लंबित रहने के दौरान पक्षों के बीच एक समझौता हुआ जिसके अनुसार यह सहमति हुई कि यदि प्रतिवादी ने एक निश्चित अवधि के भीतर कुछ राशि जमा कर दी, तो एक पक्षीय डिक्री को रद्द कर दिया जाएगा और मुकदमा बहाल कर दिया जाएगा। इसमें एक डिफॉल्ट क्लॉज भी था, जिसमें कहा गया था कि यदि निर्दिष्ट अवधि के भीतर राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो विविध आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। यह आदेश भी कोई डिक्री नहीं था. इसी तरह गोबर्धन सिंह (एआईआर 1972 सभी 246) (एफबी) और न्यू बंगेश्री बस्तरालय के मामले (एआईआर 1976 कैल 335) (सुप्रा) में आदेश डिक्री नहीं बने। इसके बाद श्री चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य मामले जोधायन बनाम बाबू राम का संदर्भ दियाएआईआर 1983 एससी 57. उस मामले में रुपये के भुगतान पर वादी के पक्ष में प्रीएम्प्शन सूट में कब्जे की डिक्री पारित की गई थी। 17,936.25पी. डिक्री धारक ने रुपये की राशि जमा कर दी। 17,936/- लेकिन

गलती से पच्चीस पैसे जमा नहीं किये। बाद में, उन्होंने उक्त राशि जमा कर दी, लेकिन समय से परे। इसके बाद उन्हें और रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया। द्वितीय अपील में 500/- का भुगतान किया जो उन्होंने निर्धारित समय के भीतर किया। निष्पादन में निर्णय-ऋणी द्वारा आपत्ति की गई कि डिक्री निष्पादित नहीं की जा सकती क्योंकि डिक्री धारक द्वारा पूरी राशि जमा नहीं की गई है। निष्पादन न्यायालय ने माना कि गलती वास्तविक थी और परिणामस्वरूप आपत्ति को खारिज कर दिया गया। पहली अपील में निष्पादन न्यायालय के आदेश को उलट दिया गया और दूसरी अपील में प्रथम अपीलीय न्यायालय के दृष्टिकोण की पुष्टि की गई। डिक्री धारक की आगे की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कम जमा राशि अपीलकर्ता की वास्तविक गलती के कारण थी। इसलिए, इसने अपील स्वीकार कर ली और निष्पादन न्यायालय के आदेश को बहाल कर दिया। मेरे विचार में उपरोक्त टिप्पणियों को उस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उपरोक्त सभी मामले अलग-अलग हैं और उनमें अनुपात इस मामले पर लागू नहीं होगा। इसलिए, मेरा विचार है कि किसी पक्ष द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर कुछ राशि के भुगतान पर कब्जे के लिए सशर्त डिक्री के मामले में, न्यायालय पर्याप्त कारण के लिए संहिता की धारा 148 के तहत भुगतान के लिए समय बढ़ाने का हकदार नहीं है। यदि निर्धारित समय के भीतर राशि जमा नहीं की जाती है।

7. वर्तमान मामले में आवेदक द्वारा अंतिम किस्त समय पर जमा नहीं की गई। उन्होंने यह स्वीकार किया कि उनके पास निर्धारित अवधि के भीतर जमा करने के लिए पैसे नहीं थे। इस प्रश्न पर जाने की आवश्यकता नहीं है कि वह राशि क्यों जमा नहीं कर सका क्योंकि मेरी राय है कि वर्तमान मामले में संहिता की धारा 148 के तहत राशि जमा करने में हुई देरी को माफ नहीं किया जा सकता है। परिणामस्वरूप आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त कारणों से मुझे आवेदन में कोई योग्यता नहीं मिली और मैं इसे खारिज करता हूं। मूल्य के हिसाब से कोई आर्डर नहीं।

अस्वीकरण

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अमित

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी नूंह